दिल्ली विद्युत बोर्ड की कार्यकुशलता

4695. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अप्रैल, 1998 के दैनिक "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "कुमारमंगलम ब्लेम्स इट ऑन इनएफिशिएन्ट डीवीबी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार को दिल्ली विद्युत बोर्ड की कार्यकुशलता पर संदेह है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त बोर्ड की कार्यकुशलता में व्यापक सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उठाए गए इन कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ङ) दिल्ली में अच्छी गुणवत्ता की विद्युत की आपूर्ति और वितरण करने तथा दिल्ली के भीतर प्रत्येक फीडरों में वोल्टता का अनुरक्षण करने का कार्य और जिम्मेवारी अन्य राज्य बिजली बोर्ड के समान दिल्ली सरकार के नियन्त्रणाधीन दिल्ली विद्युत बोर्ड की है।

डी०वी०बी० की पारेषण एवं वितरण हानियां जो वर्ष 1994-95 में 36.56% थीं वर्ष 1995-96 में बढ़कर 40.57% हो गई है।

दिल्ली में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा 25.3.1998 को दिल्ली के मुख्य मंत्री के साथ आयोजित बैठक में की गई थी। बैठक में क्रियान्वयन हेतु एक कार्य-योजना को अन्तिम रूप प्रदान किया गया था। इसकी केन्द्रीय विद्युत सचिव और दिल्ली के मुख्य सचिव की 6.7.1998 को हुई बैठक में समीक्षा की गई थी। सरकार ने शंट कैपेसिटरों की अधिष्ठापना हेतु पावरग्रिड कारपोरेशन से सहायता, बढ़ती हुई विद्युत संबंधी अदत्त देय राशियों के बावजूद भी केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों से विद्युत आपूर्ति के अनुरक्षण तथा डी०वी०बी० की अपर्याप्त पारेषण एवं वितरण प्रणाली की प्रणालीगत बाधाओं की शर्त पर उत्तरी ग्रिड से अधिकतम सम्मानित विद्युत उपलब्ध कराके दिल्ली सरकार/दिल्ली विद्युत बोर्ड को सभी सम्भव सहायता प्रदान की है। सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 की शर्तों पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना करने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली विद्युत बोर्ड को सलाह प्रदान की है।

Loss on account of excess of power generation

4696. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that India losses an estimated Rs. 250 crore every year because of excess generation of power as the generating units continue to generate electricity even when the demand falls during certain part of the year merely to meet their generating targets without taking into account the final consumption;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether these units do so to keep their plant load factor high even when it is not warranted; and

(d) the steps taken by Government to stop the wastage of power and money on such avoidable generation of power?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) to (c) Some of the generating units have been generating in excess of demand resulting in high frequency operation of the regional grids, particularly in Eastern Region, where availability of power is in excess of demand. The Eastern Region Electricity Board has been persuing its efforts to maintain grid discipline.

(d) The following steps have been taken to utilise surplus availability of power and to economise operations;

(i) Maximising export of power from surplus to deficit regions.

(ii) Scheduling the generation and cyclic shutdown of units in Eastern Region.

(iii) Staggering of load to flatten the load curve.

(iv) Formulation of an availability tariff regime.